पूरा समाधान हो जायगा। लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उस से मालूम होता है कि अभी तक बिहार में सिंचाई की गई जमीन केवल 19 प्रतिशत थी और पश्चिम बंगाल में 16 प्रतिशत थी, इतनी ही जमीन पर सिंचाई का बंदोबस्त किया जा सका है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि बंगाल और बिहार में लोगों ने गेहूं और चना खाना सीख लिया है तो वहां की सम्पूर्ण खेती लायक जमीन में गेहूं व चना पैदा करने के लिए क्या वे पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बिहार के कितने ऐसे क्षेत्र में जिसको आमतौर से समझा जाता था कि वह धान पैदा करने वाले क्षेत्र हैं वहां पर इस साल बहुत अच्छी गेहूं की फसल हुई है। जहां तक चने का सवाल है बिहार बहुत जमाने से चने की बहुत अच्छी फसल पैदा करता रहा है। और भी अधिक स्थानों में और क्षेत्रों में एक ही फसल नहीं बल्कि एक से अधिक फसल पैदा की जा सके इस के लिए तेजी से प्रबन्ध हो रहा है। बिहार सरकार जितनी तेजी से काम करेगी हम उतनी उनको उस में सहायता करेंगे।

श्री वेणीशंकर शर्मा : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे किसान साल में दो, दो और तीन, तीन फसलें पैदा करने लगे हैं। अभी जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र (बांका) में गया था तो मैंने देखा कि वहां हमारे किसान जगह-जगह जहां पानी की व्यवस्था है ताइचून धान लगा रहे हैं। आज तक मैंने इन दिनों खेतों में कहीं धान नहीं देखा था और मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां आज कल ताइचून धान रोपा जाने के कारण जो खेतों में हरियाली देखने को नसीब हो रही है जोकि इस से पहले कभी देखने में नहीं आई थी तो क्या माननीय मन्त्री वहां सिंचाई के लिए किसानों को और भी अधिक मात्रा में पानी मुहैया किये जाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि वैसा करने से हमारे किसान बहुत आसानी से साल में तीन फसल पैदा कर सकेंगे। प्रश्न केवल पानी का है। मैंने बराबर मन्त्री महोदय से प्रार्थना की है, और आज भी फिर उन से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वे अपनी कैबिनेट से लड़ झगड़ कर पानी की व्यवस्था के लिए काफी रुपयों का इन्तजाम करें। चूंकि वे स्वयं भी बिहार से आते हैं इस लिये हमें उन पर बड़ा फख्र है। किन्तु अभी-अभी 1440 नं० के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि बिहार में प्राइवेट ट्यूबवेल 8,000 और स्टेट ट्यूबवेल 70 लगाये जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है वहां 570 स्टेट ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल में 450 लगाये जा रहे हैं। आखिर बिहार के साथ क्यों सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है कि वहां सिर्फ 70 ट्यूबवेल ही लगाये जा रहे हैं?

श्री जगजीवन राम : पता नहीं कैसे माननीय सदस्य को सौतेली मां की याद हो आई। बराबर यह बात रही है कि बिहार की जितनी क्षमता खर्च करने की होगी और किसान कितना उतावलापन दिखलायेंगे उतना लैंड डेवेलपमेंट बैंक से उन्हें कर्जा मिल जायेगा?

Incentive Wages in Public Undertakings

*1452. **SHRI RABI RAY** : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the preliminary studies conducted by the Labour Bureau have shown that where incentive wages have been introduced in the public sector undertakings, labour productivity has gone up ;

(b) if so, whether it is a fact that this problem was considered at a Conference of the Heads of public sector undertakings held on the 19th April, 1968 ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) to (c). The question was discussed at

the Meeting of Heads of Public Sector Undertakings held on 19.4.1968 with a view to obtaining their consent to certain data being made available to the Director Labour Bureau who has been asked to collect the necessary information. The Heads of Public Sector Undertakings have agreed to this proposal. I may add that in April information was collected but it was not very scientific.

श्री रवि राय : मैं पूछना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय मानते हैं कि इस तरह का इन्सेन्टिव देने से पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तब जो पिछली इंडियन लेवर कांफरेंस हुई थी उस में इस पर बहस हुई थी ? यदि हुई थी तो क्या फैसला हुआ ?

श्री हाथी : इस पर तो बहस नहीं हुई है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी का समीकरण करने के बारे में तय किया गया है ।

श्री रवि राय : कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स जो तैयार किया गया है वह प्रोडक्शन पर किया गया है, तो कौन कौन साल की कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स को बेसिस माना गया है ?

SHRI HATHI : This is connected with productivity and if incentive schemes are given to the worker, if he produces more then he gets more. The idea is to have the wage fixed first—the basic wage, and then a portion is to be added as cost of living and third, according to the greater production, an incentive. These three combined should form the wage, and for that purpose, we want to find out where this incentive can be worked and for what. Certain data have to be collected, and therefore, we said at this meeting of the heads of public sector undertakings that where scientific data have been collected they may be supplied to the Labour Board. They have agreed.

श्री रवि राय : डेटा जो कलेक्ट है क्या आप टेबल पर रक्खेंगे ?

श्री हाथी : अभी उस को कलेक्ट करना है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जब अभी इन्सेन्टिव स्कीम अमल में लानी है तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सभी मजदूर संगठनों के साथ बात चीत कर के और उन की सहमति से यह स्कीम अमल में लाई जायेगी, यूनियन को मान्यता है या नहीं है, इस किस्म के झंझट में न जाते हुए सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात ही दृष्टि के सामने रक्खी जायेगी ?

SHRI HATHI : In fact that is what I said before, and certainly the unions will be taken into confidence before this scheme is discussed ; definitely.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है मान्यता है या नहीं इस झंझट में न जाते हुए...

SHRI HATHI : Whatever is the plan, the workers will be taken into confidence.

SHRI K. NARAYANA RAO : Mr. Speaker, Sir, the public sector undertakings have been the subject of criticism all these years. In view of this, and also in view of the fact that they have not registered much improvement in spite of the criticisms, may I know from the hon. Minister whether they would consider that the workers' participation in profit-sharing can be a better solution out of this malaise in the public sector undertakings ?

SHRI HATHI : Not this actually, but in the last Indian Labour Conference, this question was considered as to how best the industrial relations in the public sector undertakings can be improved, and a bi-partite team might go into it.

श्री मुहम्मद इस्माइल : हैवी इंजीनिअरिंग कारपोरेशन रांची में मशीनें तैयार होती हैं। मैंने सुना है वहां पर कोई स्टडी टीम बनाई गई है प्रोडक्शन के लिये । मैं जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है या नहीं । अगर नहीं बनाई गई है तो क्या किसी इन्सेंटिव स्कीम को बनाने की प्लैन आप कर रहे हैं जिस से प्रोडक्शन ज्यादा हो ? आप ने कोई इंस्ट्रक्शन इस सम्बन्ध में दिया है या नहीं ?

श्री हाथी : अभी तो सिर्फ कलेक्शन आफ डेटा का सवाल है । इस के लिये हमने वहां से भी डेटा मंगाया है उस के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

SHRI SHANTILAL SHAH : Will the Government see that in framing the incentive schemes they are not utilised to depress the wage for the workers and that these schemes are not utilised to get rid of someone else ?

SHRI HATHI : There is no question of getting rid of any workers. The question was that the more they produce, the more they get : they get the basic wage plus the cost of living allowance plus something by way of incentive if they produce more. That is the whole idea.

SHRI RANGA : It is quite clear that the Minister has tried to make us understand what is meant by the incentive scheme and what are its limitations. From ancient time—of Nandaji and Pandit Nehru—they have been talking of this workers' participation or partnership in the so-called profits which do not exist and also the incentive schemes. Why is it that Government are taking so many years to study this matter, sort out all the facts that they have at their disposal and then there after alone to come to a decision as to where, to what extent and in what manner this incentive scheme should be introduced in the public sector undertakings which are expected to set an example to all other entrepreneurs as ideal entrepreneurs ?

SHRI HATHI : The different industries will have to be looked into. It is not that one incentive scheme could apply to all. It will have to depend upon each particular industry because the conditions differ and the methods of production differ and that takes time.

SHRI D. C. SHARMA : We have very intimate relations with Yugoslavia and I think the incentive scheme has been worked much better in Yugoslavia, so far as I know, than in many of the democratic and other types of countries. May I, therefore, ask the hon. Minister whether he will be prepared to consider and try the Yugoslavian experiment so far as the public sector undertakings are concerned, so that the so-called Managers and Chairmen who know nothing about the public undertakings have as much of stake in those undertakings as the workers have ?

SHRI HATHI : I have not studied that scheme. So, I cannot say.

श्री देवेन सेन : मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्सेंटिव स्कीम तैयार हुई है वह सभी मजदूरों की कटेगरीज पर लागू होगी या कुछ मजदूरों की कटेगरीज पर ही लागू होगी ।

श्री हाथी : अभी लागू करने की कोई बात तो है नहीं । कैसे कलेक्शन आफ डेटा हो इस के लिये प्रश्न है । सब पर लागू करना है या नहीं, यह बात नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

*1453. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उर्वरकों के वितरण के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि 1966-67 में 57 करोड़ रुपये से घटाकर 1967-68 में 19 करोड़ रुपये कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमोनियम सल्फेट की कीमत प्रति क्विन्टल 405 रुपये से बढ़कर 492 रुपये हो गई है; और

(घ) इस मूल्य वृद्धि को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि किसान अधिक अनाज का उत्पादन कर सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं देती है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार उन्हें उर्वरकों के विपणन व वितरण के लिये भी अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है ।